IF UNDELIVERED
PLEASE RETURN TO
मारवाड़ का मित्र
:: Regd. Office ::
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - जालोर (343041)

सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

मारवाड़ का मित्र

Www.MarwadkaMitra.in

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25 UDYAM-RJ-19-0033346

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

वर्ष 23 | अंक 10 | सांचौर, गुरुवार 15 मई 2025 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव, | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

आठ जिलों में गठित होगे नवीन सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में श्रीअन्न के उत्पाद आमजन को आसानी से उपलब्ध करवाने एवं प्रचलन में लाने के लिए प्रत्येक जिले में प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर मिलेटस उत्पाट आउटलेटस खोलने की बजट घोषणा की पालना में 8 जिलों में नवीन सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार गठित करने के निर्देश सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा समस्त अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को पत्र भेजकर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक बालोतरा, ब्यावर, डीग, खैरथल तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन, फलौदी एवं सलूम्बर जिले में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार का गठन होगा, जिसके लिए न्यूनतम हिस्सा राशि 2 लाख रुपए निर्धारित की गई हैं, साथ

ही, जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार केन्द्रीय स्तर की सहकारी संस्था होने के चलते कम से कम 5 सदस्य स्वयं सहकारी सोसायटी होना आवश्यक है। इसके अलावा नवीन जिलों में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार गठन करने से पूर्व अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा मूल जिले में कार्यरत सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों के व्यक्तिगत सदस्य, सदस्य सहकारी संस्थाओं की संख्या एवं इनकी जमा हिस्सा राशि के साथ मूल जिले से अलग हुए नये जिले में भण्डार के सदस्य एवं हिस्सा राशि की सूचना के आधार पर नवीन भण्डार के गठन का निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया हैं, यह सूचना सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय द्वारा 15 मई तक चाही गई हैं ।

उप रजिस्ट्रार से मांगी गई सर्वे रिपोर्ट

सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार गठन से पूर्व उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां से सर्वे रिपोर्ट 31 मई तक सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा मांगी गई हैं, जिसमें भण्डार गठन से लाभान्वित होने वाली जिले की सम्पूर्ण ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के साथ प्रस्तावित जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार के लिये जिले में कार्यरत प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, प्राथमिक महिला सहकारी समितियां, अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या तथा अ श्रेणी के सदस्यों से न्यूनतम हिस्सा राशि सहजता से जमा की जाने की संभावना सहित उपभोक्ता व्यवसाय एवं मेडिकल व्यवसाय की संभावना रिपोर्ट एवं अर्जित होने वाला लाभ के अलावा जिला प्रशासन द्वारा निशुल्क भूमि/भवन आवंटित करने की संभावना का भी उल्लेख सर्वे रिपोर्ट में करने के लिए निर्देशित किया गया हैं ।

30 मई तक खण्डीय रजिस्ट्रार करे पंजीयन की कार्यवाही

सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय की ओर से जारी पत्र के मुताबिक उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट में नवीन जिले में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार के गठन की वायबिलिटी होने पर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 5 एवं 6 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन या गठन की कार्यवाही की जा सकती हैं, जिसके लिए 30 मई 2025 तक की समयावधि निर्धारित की गई हैं ।

भूमि विकास बैंक के ऋणधारकों को राहत

झुंझुनूं । राज्य सरकार ने सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों और ऋणधारकों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 को लागू कर दिया है। यह योजना मुख्यमंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुरूप बनाई गई है। बैंक सचिव संजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना उन सभी ऋण खातों पर लागू होगी जो 1 जुलाई 2024 को अवधिपार श्रेणी में वर्गीकृत थे। हालांकि, वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत वितरित ऋण इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। यह योजना 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी।

बुनकरों को नगद पुरस्कार देने के लिए आवेदन आमंत्रित

अजमेर,। राज्य के हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में भी बुनकरों को नगद पुरस्कार देने का प्रावधान किया है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबन्धक धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि इसके अनुसार जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए जिले की सीमा में कार्यरत हथकरघा बुनकरों एवं समितियों से आवेदन पत्र आमंत्रित है। इसके लिए पिछले 3 वर्षों से हाथकरघा पर बुनाई कार्य कर रहे बुनकर एवं सहकारी समितियां पात्र है। उन्हें गत 3 वर्षों में इस पुरस्कार के लिए चयनित नहीं किया गया हो। पात्र हथकरघा बुनकर एवं समितियां अपना आवेदन 16 जून तक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र आरपीएससी के पास जयपुर रोड अजमेर में जमा करा सकते है। आवेदन फार्म जिला उद्योग केन्द्र अजमेर कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

आरबीआई ने कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों के लिए मानदंडों में ढील दी

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य मार्ग से कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए मानदंडों में ढील दी है। रिज़र्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि एफपीआई को अब अल्पकालिक निवेश और सांद्रता सीमाओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। सांद्रता सीमा का मतलब है कि एक एफपीआई किसी एक कंपनी या समूह में कितना निवेश कर सकता है। एफपीआई के लिए निवेश और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

यदि आपको अपने क्षेत्र से लगाव है तो कृपया मारवाड़ का मित्र हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र के लिए मारवाड़ आंचल के विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक कला,संस्कृति आदि अन्य सामाजिक,शैक्षणिक, व्यवसायिक स्थलों पर लेख,कथा, कहानी विवरण आदि हमें अवश्य प्रकाशनार्थ भिजवाने । प्रकाशन सामग्री के साथ संबंधित स्थल का फोटो भी एवं आपका फोटो भी अवश्य भिजवाएं । सामाजिक,शैक्षणिक, व्यवसायिक स्थलों पर लेख,कथा, कहानी विवरण आदि हमें अवश्य प्रकाशनार्थ भिजवाने । प्रकाशन सामग्री के साथ संबंधित स्थल का फोटो भी एवं आपका फोटो भी अवश्य भिजवाएं ।

-संपादक

सीड एक्ट के तहत भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का गठन

सहकारी नेटवर्क के सहारे किसानों को मिलेंगे उन्नत किस्म के बीज

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली, कम जमीन में ज्यादा पैदावार के लिए उन्नत बीज का होना जरूरी है। यह तभी संभव हो सकता है जब परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे किसानों को आसानी से परिष्कृत एवं सस्ते बीज उपलब्ध कराए जाएं। केंद्र सरकार ने इसके लिए पहल की है। भारत ब्रांड की सफलता के बाद सहकारिता के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य है। सीड एक्ट के तहत भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) का गठन किया गया है, जो देशभर में फैले सहकारी नेटवर्क के जरिये भारत बीज नाम से उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन, खरीद एवं किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित कर सके। इससे किसानों को नकली एवं खराब बीजों से छुटकारा मिल सकेगा। देश

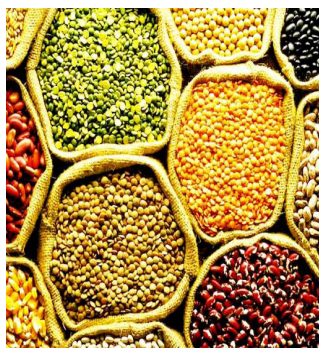

में अभी तक ऐसी कोई राष्ट्रीय संस्था नहीं थी, जो बीज उत्पादन से लेकर भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, विपणन और अनुसंधान तक समग्रता में काम कर सके। यह संस्था पूरी तरह से सदस्य किसानों के लिए समर्पित रहेगी। इसके जरिये बीज उत्पादन एवं बिक्री से होने वाली आय का 80 प्रतिशत संस्था के सदस्य किसानों को दिया जाएगा। देश में अभी 47 प्रतिशत क्षेत्रों में ही गुणवत्ता वाले बीज का इस्तेमाल हो रहा है। बीबीएसएसएल का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के तहत वंचित क्षेत्र में भी पैदावार बढ़ाना है। अभी कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर तीन सहकारी समितियां हैं, जिनका काम उन्नत बीजों के उत्पादन एवं इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। बीबीएसएसएल की जिम्मेदारी उपज में सुधार के लिए स्वदेशी बीजों के संरक्षण संवर्धन के लिए काम करना है। संस्था को चालू वित्त वर्ष में 270 करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही 2032 तक 20 लाख टन बीजों की बिक्री के साथ 18 हजार करोड़ रुपये का कारोबार करना है। उन्नत बीजों की खेती के लिए पैक्सों के जरिये किसानों का चयन होगा। उन्हें सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उन्हें इसके माध्यम से समय पर उन्नत एवं प्रमाणित बीज मिलेगा, जिससे उपज और आय में वृद्धि होगी। बीज उत्पादक के रूप में उनकी पहचान बनेगी। किसानों के बीच लाभांश वितरण की भी पारदर्शी व्यवस्था है। संस्था की सदस्य समितियों को भी उनकी अंश पूंजी पर अधिकतम 20 प्रतिशत तक लाभांश दिया जाएगा। अभी तक संस्था में 24 राज्यों की 21 हजार से अधिक सहकारी समितियां सदस्य बन चुकी हैं। संस्था ने काम शुरू भी कर दिया है। मूंगफली, गेहूं, जई और बरसीम के बीज का उत्पादन और बिक्री होने लगी है। खरीफ मौसम में धान, चना, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार, मक्का एवं बींस की विभिन्न किस्मों के बीज उपलब्ध कराने की तैयारी है। उत्पादन के बाद बीजों की बिक्री एमएसपी या बाजार मूल्य में जो भी ज्यादा हो, उस पर होगी। इसके अतिरिक्त बीज निगम और मंडियों में बीजों के दाम का भी आकलन किया जाएगा। जो भी ज्यादा होगा, उसी दाम पर बिक्री होगी।

राजफैड बढ़ाए जिलेवार एवं क्रय केन्द्रवार पंजीयन लक्ष्य की कैपिंग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को समर्थन मूल्य खरीद का अधिक से अधिक लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सरसों एवं चना खरीद हेतु आवंटित कृषक पंजीयन लक्ष्य को ऐसे स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाए, जहां किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर जिन्स विक्रय में अधिक रूचि ली जा रही है। श्रीमती राजपाल ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बाजार भाव अधिक होने के कारण पर्याप्त मात्रा में किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर जिन्स विक्रय के लिए पंजीयन करवाया गया है। जबकि, कई क्षेत्रों में पर्याप्त उत्पादन नहीं होने के कारण पंजीयन की संख्या कम है। अतरू पंजीयन लक्ष्यों को स्थानान्तरित किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि राजफैड के स्तर से जिलेवार एवं क्रय केन्द्रवार पंजीयन लक्ष्य की कैपिंग को बढ़ाया जाए, जिससे भारत सरकार द्वारा निर्धारित खरीद लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। राजफैड के प्रबंध निदेशक श्री मोहम्मद जुनैद ने बताया कि कई केन्द्रों की पंजीयन क्षमता पूर्ण हो चुकी है। ऐसे में इन केन्द्रों पर वर्तमान में आवंटित पंजीकरण क्षमता को दोगुना किया जाएगा। वहीं, जहां पंजीकरण प्रारम्भ होने के बाद नये केन्द्र स्वीकृत किए गए और जिनकी पंजीकरण क्षमता शून्य है, को 12 मई, 2025 से सरसों एवं चना हेतु 100-100 पंजीकरण के लक्ष्य आवंटित किये जाएंगे। इससे निर्धारित खरीद लक्ष्यों की पूर्ति हो सकेगी तथा किसानों को समर्थन मूल्य खरीद का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

भेडाना ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड भेडाना

एक सब के लिए, सब एक के लिए

सहकारी आंदोलन, किसानों एवं ग्रामीणों को समर्पित प्रगतिशील सहकारी सोसायटी

सहकारिता का ध्येय वाक्य 'एक सब के लिए, सब एक के लिए'सब '

किसान भाई, अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठावें। समिति कार्यक्षेत्र के पशुपालक, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समिति स्तर पर संपर्क करें।

प्रागाराम चौधरी
अध्यक्ष

मदन पटेल
व्यवस्थापक

सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव का तीन दिवसीय जालोर-सिरोही दौरा प्रस्तावित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव एवं सहकारिता विभाग पंजीयक श्रीमती मंजू राजपाल का 15 मई से लेकर 17 मई तक जालोर एवं सिरोही जिले का दौरा प्रस्तावित हैं, इस संबंध मिली जानकारी के अनुसार, 15, 16 एवं 17 मई को सिरोही एवं जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय में बैठक के साथ विभिन्न शाखाओं एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों का निरीक्षण भी प्रस्तावित हैं, वही सिरोही सीसीबी प्रबंध निदेशक ने सहकारिता विभाग पंजीयक की प्रस्तावित बैठक के संबंध में पत्र जारी कर शाखा एवं समिति कार्यालय की पूर्ण साफ-सफाई सुनिश्चित करने के साथ सभी रिकॉर्ड को व्यवस्थित रूप से अद्यतन व प्रस्तुत करने योग्य स्थिति में रखने एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत संभावित कार्यक्रमों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं । हालांकि विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, केन्द्रीय सहकारी बैंकों सहित राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. की एक मुश्त समझौता योजना के बारे में समीक्षा बैठक आहुत करने की जानकारी मिल रही हैं

संभाग और जिला स्तर पर भी होने चाहिए मसाला मेले जैसे आयोजन - सहकारिता मंत्री

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला की चर्चा पूरे प्रदेश में होती है। इस तरह के मेलों का आयोजन संभाग और जिला स्तर पर भी होना चाहिए। ऐसे आयोजनों से सहकारी संस्थाओं द्वारा तैयार उत्पादों को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है। उन्होंने कहा कि हम सब सहकारिता के ध्येय वाक्य 'एक सबके लिए, सब एक के लिए' को आत्मसात कर सहकारी सेक्टर को मजबूत करें ताकि देश के हर नागरिक को इसका लाभ मिले। सहकारिता मंत्री ने जवाहर कला केन्द्र के दक्षिण परिसर में प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल की उपस्थिति में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का दीप प्रज्वलन कर तथा फीता काटकर शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की स्वदेशी की भावना को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के

आयोजन जरूरी हैं। इससे पूर्व सहकारिता मंत्री एवं प्रमुख शासन सचिव ने मेले में लगी स्टॉल्स का अवलोकन कर देश-प्रदेश की सहकारी समितियों द्वारा विक्रय के लिए लाए गए मसालों एवं अन्य उत्पादों की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफैड) द्वारा वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष मसाला मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण मसालों के साथ ही अन्य उत्पाद उचित दाम पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध होते हैं, जिससे यह जयपुरवासियों की खास पसंद बन चुका है। मसाला मेले के आयोजन से आमजन का सहकारी उत्पादों पर विश्वास भी बढ़ रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 की थीम पर 18 मई तक यह मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले में राजस्थान के साथ ही केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों की सहकारी समितियों के उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। साबुत और पीसे हुए मसालों के साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों के विशिष्ट उत्पाद राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में बिक्री के लिए उपलब्ध कराये गए हैं। मेले में आगन्तुक ग्राहकों के लिए प्रतिदिन लक्की ड्रॉ एवं समापन पर मेगा बम्पर ड्रॉ की व्यवस्था भी की गई है। मेले के शुभारम्भ के अवसर पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) एवं कॉनफैड की प्रबंध निदेशक श्रीमती शिल्पी पांडे सहित विभाग के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं सहकारजन उपस्थित रहे।

पोर्टल और पोस्टर का किया विमोचन

सहकारिता मंत्री ने इस अवसर पर राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा तैयार करवाए गए पोर्टल का रिमोट का बटन दबाकर विमोचन किया। यह पोर्टल मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने विभिन्न प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के अध्यक्षों की उपस्थिति में योजना के पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही, पांच ऋणी किसानों को ऋण राहत प्रमाण पत्र भी वितरित किए। श्री दक ने इस अवसर पर दो प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां को राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के माइक्रो एटीएम वितरित किए तथा 'म्हारो खातों, म्हारो बैंक' अभियान के तहत बचत खाते खोले जाने हेतु पोस्टर का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की भावना है कि किसान आगे बढ़े, इसीलिए भूमि विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना लाई गई है। श्री दक ने कहा कि 'म्हारो खातो, म्हारो बैंक' अभियान का नाम हर व्यक्ति की जुबां पर आना चाहिए।

उत्पादकता बढ़ाने की कवायद

भारत ने हाल ही में चावल की दो जीनोम-संवर्धित किस्में जारी की हैं और यह कृषि क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लिएज 1 (एसडीएन1) जीनोम परिवर्तन तकनीक की मदद से विकसित डीआरआर धान 100 (कमला) और पूसा डीएसटी राइस 1 नामक ये किस्में न केवल 30 फीसदी तक अधिक पैदावार का वादा करती हैं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण को हानि तथा क्षेत्रीय कृषि असंतुलन जैसी चुनौतियों से निपटने में भी मददगार साबित हो सकती है। चावल की ये दोनों किस्में अपनी मूल किस्मों यानी क्रमश; सांबा मंसूरी (बीपीटी 5204) और कॉटनडोरा सन्नालू (एमटीयू-1010) की तुलना में बेहतर परिणामों का वादा करती हैं। एक बात जो इन दोनों नई किस्मों को अधिक आकर्षक बनाती है वह है तैयार होने की 15 से 20 दिन की कम अवधि। इसके चलते फसलों को जल्दी बदला जा सकता है और जमीन का अधिक किफायती इस्तेमाल संभव हो सकता है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पानी की कम जरूरत और उच्च नाइट्रोजन-उपयोग दक्षता भारतीय कृषि की एक बड़ी चुनौती को हल कर सकता है, जो है भूजल का अत्यधिक दोहन। खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में। ये दोनों राज्य चावल के बड़े उत्पादक हैं और भूजल की सबसे अधिक क्षति वाले राज्यों में भी यही शामिल हैं क्योंकि यहां दशकों से धान की खेती हो रही है जिसमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ये जीनोम-संवर्धित चावल की किस्में सूखे से काफी हद तक सुरक्षित हैं और मिट्टी की खराब स्थिति में भी बची रह सकती हैं। ऐसे में ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, तटीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये वे इलाके हैं जो ऐतिहासिक रूप से धान की कम उत्पादकता के लिए जाने जाते हैं। ऐसा इन राज्यों में मिट्टी और जलवायु के चुनौतीपूर्ण हालात के कारण है। इन इलाकों में धान की खेती को प्रोत्साहन देने से चावल के उत्पादन क्षेत्र का विस्तार होगा। इससे पारिस्थितिकी पर दबाव कम होगा क्योंकि कुछ इलाकों में धान की अत्यधिक खेती की जाती है। इससे कृषि अर्थव्यवस्था में समता आएगी। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जीनोम-संवर्धित करने की तकनीक मसलन एसडीएन1 आदि पारंपरिक जीन संवर्धित प्रणाली से अलग है क्योंकि इसमें बाहरी डीएनए नहीं शामिल किया जाता। इसका अर्थ यह हुआ कि नियामकीय और नैतिक स्तर पर बहुत बाधाएं नहीं होतीं, जनता में इनकी स्वीकार्यता अधिक होती है और इनको अधिक तेजी से अपनाया जा सकता है। विज्ञान के साथ-साथ नीतिगत व्यवस्था को उन्नत बनाने की आवश्यकता है। सरकारी खरीद करने वाली एजेंसियों को इन किस्मों को चिह्नित करना चाहिए और उन्हें सरकारी खरीद तथा वितरण प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। किसानों को प्रशिक्षित करने तथा खेत के स्तर पर इनके इस्तेमाल के स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करके जैव सुरक्षा चिंताओं को दूर किया जा सकता है। देश की जरूरतों को देखते हुए हमें जीन संवर्धित फसलों पर अपने रुख की समीक्षा करनी चाहिए। साल 2022 में सरकार ने जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड, डीएमएच-11 को मंजूरी दी थी। यह एक ऐतिहासिक कदम था जहां जीन संवर्धित फसलों को लेकर सकारात्मकता दिखाई गई थी। समुचित नियमन और वैज्ञानिक पारदर्शिता के साथ जीएम फसलें उत्पादकता बढ़ा सकती हैं। इनसे जैविक दबाव को लेकर प्रतिरोध कम हो सकता है और इनपुट की लागत कम हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे जीएम फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करें। सरकार को इस बारे में समूची संभावनाओं को भी खंगालना चाहिए। इतना ही नहीं जैव प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का लाभ लेने के लिए भारत को कृषि शोध एवं विकास में निवेश बढ़ाना चाहिए, जैव प्रौद्योगिकी संस्थाओं के लिए संस्थागत सहायता बढ़ानी चाहिए और जलवायु के प्रति टिकाऊपन को खाद्य सुरक्षा नीतियों में शामिल करना चाहिए। कृषि शोध और विकास व्यय के लिए वर्तमान बजटीय आवंटन केवल 10,466 करोड़ रुपये है और अगले दो-तीन सालों में इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि जैव प्रौद्योगिकी अब दीर्घकालिक रूप से खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

प्राथमिक स्तर से ही अनिवार्य हो कृषि शिक्षा

> **इस देश में राजनीतिक अकर्मण्यता और आधुनिक विकास के तकनीकी, प्रौद्योगिकीय कोण पर ही केंद्रित रहने की शासकीय महत्वाकांक्षाओं ने उद्योगों को चहुंदिश प्रश्रय दिया और इसकी तुलना में कृषि क्षेत्र को उपेक्षित छोड़ दिया गया। खेती-किसानी की ऐसी उपेक्षा का प्रभाव भारतीय शिक्षा नीति पर भी पड़ा। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में कृषि संबंधित विषयवस्तु अदृश्य है।**

जीवन और जीवन के वास्तविक रूप शरीर व मन के स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक आवश्यक व अनुकूल पर्यावरण है। ऐसी अनुकूलता में भी सबसे महत्वपूर्ण है प्राकृतिक जल और भोजन। यह मानव को तब ही सहजता से उपलब्ध हो सकता है जब देश-विदेश में कृषि की समुचित व्यवस्था हो। मनुष्य के जीवन में प्राकृतिक व पारंपरिक कृषि व्यवस्था अत्यंत अनिवार्य है। इस देश में राजनीतिक अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार और आधुनिक विकास के तकनीकी, प्रौद्योगिकीय कोण पर ही केंद्रित रहने की शासकीय महत्वाकांक्षाओं ने उद्योगों को चहुंदिश प्रश्रय दिया और इसकी तुलना में कृषि क्षेत्र को उपेक्षित छोड़ दिया गया। खेती-किसानी की ऐसी उपेक्षा का प्रभाव भारतीय शिक्षा नीति पर भी पड़ा। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में कृषि से संबंधित विषयवस्तु अदृश्य है। छोटी असे अमरूद और बड़ी आ से आम के साथ आरंभ होनेवाली प्राथमिक शिक्षा में कृषि के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। यदि बच्चों के मन-मस्तिष्क में छोटी आयु और शिक्षण-कक्षाओं से ही कृषि ज्ञान-विज्ञान नहीं डाला जाएगा तो आगे बड़ी कक्षाओं में जाने पर वे विषय संबंधी रुचियों में से कृषि-विषय में आत्मरुचि कैसे प्रदर्शित करेंगे। कक्षा एक से लेकर बारहवीं तक पूरे बारह वर्षों की समयावधि में कक्षा-प्रति कक्षा जब उन्हें कृषि व इसके विभिन्न उपक्रमों के बारे में पढ़ाया-लिखाया जाएगा, व्यावहारिक शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और कृषि-कार्यों के संबंध में आयोजित होनेवाली विभिन्न कार्यशालाओं में जाने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा, तब ही तो वे कृषकीय कार्यों के बारे में अपेक्षित ज्ञान से संचित हो पाएंगे। ऐसा होने पर ही उनका मनोविज्ञान खेती के संपूर्ण साहित्य से सिंचित हो पाएगा। बच्चे यदि शुद्ध आहार-विहार अपनाने के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो इसका प्रमुख कारण यही है कि उन्हें बालपन से ही विद्यालयों में इस संबंध में शिक्षित नहीं किया गया। इसीलिए उन्हें कृषि वर्ग की प्रमुख फसलों, खाद्यान्नों, फल-फूल, वन-वनस्पतियों, औषधियों के गुण-दोषों की जानकारी भी नहीं है और संभवत यही कारण भी है कि वे खानपान की बुरी आदतों से ग्रस्त हैं। घर में या विद्यालयों में उन्हें इस संदर्भ में औपचारिक ढंग से ही बताया जाता है। अभिभावक, शिक्षक और नीति-नियंता ही जब कृषि क्षेत्र की उपेक्षा किए बैठे हों तो बच्चे इस बारे में अपेक्षानुरूप ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह अत्यंत विचारणीय है। देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से लेकर राज्यों के शिक्षा मंत्रालयों को इस दिशा में गंभीर होकर चिंतन-मनन करना ही होगा। इस काल के मनुष्य जीवन का दुर्भाग्य ही है कि उद्योगों, निर्माणियों, कारखानों, कार्यालयों और प्रगति संबंधी विभिन्न परियोजनाओं के लिए आए दिन वनक्षेत्र काटे जा रहे हैं। इसके लिए रोजाना ही कृषि क्षेत्र में कमी हो रही है। प्रकृति का असंतुलन कई दशकों से सार्वजनिक चिंता के केंद्र में है ही। प्राकृतिक असंतुलन के कारण जनजीवन प्रतिक्षण असुरक्षित होता जा रहा है। ऋतु की विकृक्तियां भयंकर रूप में सामने आ रही हैं। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये सभी तत्व हर दिन मलिन हो रहे हैं। परिणामस्वरूप धरती का फसल चक्र बिगड़ चुका है। फसलों की प्राकृतिक शक्ति लगभग समाप्त ही हो चुकी है। खाद्यान्न उत्पादन पूरी तरह कृत्रिम, रसायनमिश्रित और विषैले उर्वरकों व खाद पर निर्भर हो चुका है। पारंपरिक और नैसर्गिक खाद्यान्न-बीज विलुप्त होने की कगार पर हैं। ग्राम, ग्राम्य-जीवन, ग्रामीण व्यवस्थाओं का समापन अंतिम स्तर पर है। इस कालखंड में पूरी तरह सिद्ध हो चुका है कि विज्ञान केवल और केवल अभिशाप बनकर मनुष्य के सिर पर मंडरा रहा है। चारों ओर आधुनिक जीवन द्वारा उत्पन्न की गईं समस्याओं, रोगों और महामारियों की असुरक्षा फैली हुई है। जीवन का स्वाभाविक आनंद क्या होता है,
इससे मनुष्य अनभिज्ञ है। हरेक खाद्य और पेय पदार्थ शरीर का पोषण करने के बजाय उसे असाध्य रोगों से खत्म कर रहा है। देश में जितने भी कृषि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान हैं हालांकि उनमें कृषिगत विषयों का पठन-पाठन तो हो रहा है और यथासंभव प्रयोगिक प्रशिक्षण भी हो रहे हैं, पर वे कहीं न कहीं प्राकृतिक तत्वज्ञान से रहित हैं। ऐसे पठन-पाठन में कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए कृत्रिम कृषिकर्म की ही जानकारी दी जा रही है। फसलों के रक्षण-संरक्षण और उत्पादन के लिए रासायनिक पदार्थों का सहारा लिया ही लिया जा रहा है। कृषि संस्थानों, प्रतिष्ठानों और उद्यमों में बीजों पर प्रयोग का जैसा अभ्यास कुछ दशकों से किया जा रहा है, उससे कृषि उत्पादों में कोई न कोई हानिकारक तत्व स्थायी रूप में पहुंच रहा है। चूंकि यह प्रक्रिया वर्षों पुरानी हो चुकी है और कृषि से जुड़े हरेक व्यक्ति को इसमें अधिक शारीरिक व मानसिक श्रम नहीं करना पड़ता, इसलिए इसमें उत्पाद को पूर्णत हानिरहित करने के नवीन प्रयास नहीं किए जा की रहे हैं। आखिर में इसके अप्रत्याशित दुष्परिणाम मनुष्य काया ही झेल रही है। इसके अलावा जो व्यापारी गांवों, महानगरों के असंगठित क्षेत्रों में मिलावटी और जहरीला अनाज बेच रहे हैं और जितने बड़े व व्यापक स्तर पर, जितनी ज्यादा आबादी को बेच रहे हैं, मिलावटी अनाज और अनाज में प्रयोग होनेवाले प्राणघाती अवैध रसायनों का कारोबार भी उसी मात्रा में बढ़ रहा हैइस स्थिति में कर्ताधर्ताओं, शिक्षकों, अभिभावकों और देश-दुनिया के विद्वानों की मानसिक-वैचारि क अपरिपक्वता का ही संकेत मिल रहा है कि वे वास्तव में अपनी भावी पीढ़ियों के लिए कर या रहे हैं और जो उन्हें करना चाहिए वैसा वे नहीं कर रहे हैं।

- विकेश कुमार बडोला
यह लेखक के अपने विचार हैं

जल संकट मिटाने के लिए बदलाव जरूरी

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के अध्ययन के मुताबिक भारत में विकास की रफ्तार बढ़ने के साथ पानी का संकट लगातार बढ़ता जाएगा, जिससे पानी को लेकर अनेक राज्यों में मारा-मारी के हालात बने रह सकते हैं। जाहिर तौर पर पानी की खपत पिछले 40-50 वर्षों में तेजी के साथ बढ़ी है। एक दशक से पानी की मांग प्रति व्यक्ति 100 से 120 लीटर के बीच रही है जो 2025 तक बढ़कर 125 लीटर हो गई है। अब पानी की मांग 7900 करोड़ लीटर से ज्यादा हो गई है। राष्ट्रीय जल आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 1997 में जल की उपलब्धता 575 क्यूबिक किमी थी, लेकिन अब यह लगभग 500 क्यूबिक किमी है जबकि मांग 800 क्यूबिक किमी के लगभग है। यानी उपलब्धता के एवज में मांग बहुत ज्यादा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025 तक भूजल जलस्तर और घटकर 1,434 घन मीटर तथा वर्ष 2050 तक 1,219 घन मीटर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के इस आकलन पर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगले 20 सालों में भूजल के 60 फीसदी स्रोत खतरनाक हालात में पहुंच जाएंगे। क्योंकि जल की हमारी 70 फीसदी मांग भूजल के स्रोतों से पूरी होती है।

जाहिर है, तब न तो फसल उगाने के लिए पानी होगा और न तो उद्योग-धन्धों के लिए ही। खेती-किसानी तो बर्बाद होगी ही, देशा की बहुत बड़ी आबादी जल की एक-एक बूंद के लिए तरस सकती है। ऐसे में पानी की बर्बादी को रोकना जरूरी है। दुनिया में आज सबसे बड़ा संकट आतंकवाद और पर्यावरण प्रदूषण है, लेकिन 2050 में पानी संकट सबसे बड़ा संकट होगा। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि 2025 तक दुनिया की आबादी 8 अरब और 2050 तक 9 अरब को पार कर जाएगी। एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि में बसने वाले देशों की बड़ी आबादी पानी की किल्लत से जूझ रही होगी। इन देशों में सब-सहारा, कांगो, मोजांगिक, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, मयम्मार, चीन, कोरिया, घाना, केन्या, नामीबिया, अफगानिस्तान, अरब अमीरात, ईरान, ईराक, सीरिया सहित तमाम मुल्क शामिल होंगे। 2050 में साढ़े पांच अरब लोग पानी के संकट से जूझ रहे होंगे। जिस तरह से विकासशील देशों में गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है, उससे यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 के अंत तक दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही होगी, जिससे जल संकट और भी गहरा हो सकता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के नए शोध के मुताबिक भारत के 700 जिलों में से 256 जिले पानी की अतिगंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। अतिदोहन की वजह से भूजल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है जिससे कुएं, पोखर, तालाब जैसे परंपरागत जल स्रोत सूख रहे हैं। समस्या महज परंपरागत जल स्रातों का सूखने तक नहीं है, बल्कि जो भूजल बचा है वह प्रदूषित भी होता जा रहा है।

यह समस्या इतनी विकट है कि इसका समाधान सरकार भी नहीं कर पा रही है। साफपानी जानवरों को पीने के लिए न मिल पाने की वजह से जानवर बीमारियों के चपेट में आकर मर रहे हैं, इससे देश के पशुधन पर असर हो रहा है। घरेलू इस्तेमाल का पानी उन इलाकों में भी साफनहीं मिल पा रहा है, जहां तीस-चालिस साल पहले जल सदानीरा की तरह बहता और मिलता था। इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम के अनुमान के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगले 10 सालों में वाष्पीकरण की रफ्तार आज की तुलना में दुगनी हो जाएगी। इसकी वजह से नदियों और अन्य जल स्रोतों का पानी कम हो जाएगा। गर्मी बढ़ने से ध्रुवों की बर्फतेजी के साथ पिघलेगी। इससे मीठा पानी खारे समुद्र में मिल जाएगा, जिससे मीठे पानी के जलस्रोत सूखते चले जाएंगे। पानी की उपलब्धता इतनी कम हो जाएगी कि दो-चार गिलास पानी से नहाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरी समस्या जो सबसे विकराल रूप में सामने आ सकती है वह है, जल के लिए पलायन की। ऐसे स्थानों पर आबादी का विकट दबाव हो सकता है। इससे आर्थिक, सामाजिक समस्याएं पैदा होंगी। निवासियों और विस्थापितों के बीच एक संघर्ष की स्थिति बनेगी जो कई नई समस्याओं को जन्म देगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वर्ष 2030 तक 70 करोड़ लोगों को अपने क्षेत्रों से विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। केन्द्रीय मौसम विज्ञान के मुताबिक देशभर में कुल वार्षिक बारिश 1,170 मिमी होती है, और वह भी महज तीन महीने में। यदि बरसात के पानी को संरक्षित करने की योजना पर अमल करें तो पानी की किल्लत से ही निजात नहीं मिलेगी, बल्कि पानी को लेकर होने वाली राजनीति से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा । मतलब जल संरक्षण और जल के बेहतर इस्तेमाल से पानी के संकट से देश को उबारा जा सकता है। जिन इलाकों में बरसात बहुत कम होती है, वहां तो पाताल का पानी ही एक मात्र स्रोत होता है, वहां कैसे पानी की किल्लत से उबरा जाए, इस पर गौर करने की जरूरत है। ऐसे में बरसात के पानी को संरक्षित करके ही इस संकट से उबरा तो जा सकता है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के जरिए किए जा रहे पानी के मनमाना दोहन को रोकना भी बहुत जरूरी है। पानी की बढ़ती किल्लत पर आम आदमी और सरकारों का लापरवाही वाला रवैया चिंता जनक है। भविष्य में इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

> **राष्ट्रीय जल आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 1997 में जल की उपलब्धता 575 क्यूबिक किमी थी, लेकिन अब यह लगभग 500 क्यूबिक किमी है जबकि मांग 800 क्यूबिक किमी के लगभग है। यानी उपलब्धता के एवज में मांग बहुत ज्यादा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025 तक भूजल घटकर 1,434 घन मीटर तथा वर्ष 2050 तक 1,219 घन मीटर हो जाएगा।**

- अखिलेश आर्येन्द
यह लेखक के अपने विचार हैं

खरीफ फसलों की बुवाई के लिए तैयार सीमावर्ती जिलों के किसान

30 लाख हेक्टेयर में होगी खरीफ फसलों की बुवाई

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली । देश के दो प्रमुख कृषि राज्य - पुंजाब और राजस्थान - के 10 सीमावर्ती जिलों के किसान लगभग 30 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में धान, मूंग और बाजरा जैसी खरीफ फसलों का उत्पादन करते हैं। भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण किसान आगामी खरीफ सीजन को लेकर चिंतित नहीं है। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार, इन किसानों के लिए फसलों से अधिक अहमियत भारतीय सीमाओं की सुरक्षा रखती है। वहीं, युद्ध विराम की घोषणा के साथ किसानों को मानसून आने के बाद सामान्य गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के किसान और सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी नायक मल सिंह का खेत अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वे कहते हैं कि हम निराश हैं क्योंकि अगर युद्ध जारी रहता तो हम एक सीजन के लिए फसल की बलि देने के लिए तैयार थे। पाकिस्तान को एक स्थायी सबक मिल जाना चाहिए था। इसी तरह पंजाब के तरनतारन जिले के हरनाम सिंह कहते हैं कि उचित योजना होनी चाहिए क्योंकि इस साल उन्हें गेहूं की कटाई जल्दी करने के लिए कहा गया था, हालांकि फसल की समय पर बुवाई ने भी मदद की। उन्होंने कहा कि वे सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि पुलिस और सेना क्षेत्र में गश्त करती रहती है और सलाह देती है कि खेती करना ठीक है या नहीं। पंजाब के फाजिल्का जिले के किसान छिंदर पाल सीमा से सटी 60 एकड़ जमीन में खेती करते है। वे कहते हैं कि वे खेती से अपनी आजीविका कमाते हैं, इसलिए उन्हें किसी युद्ध का डर नहीं है। सरकार हमें खेत को बिना बोए छोड़ने के लिए नहीं कहती, तब तक कोई कारण नहीं है। हम यहीं पले-बढ़े हैं और हमें कोई डर नहीं है। पाल ने कहा कि कुछ घटनाओं को छोड़कर, जिस क्षेत्र में उनकी जमीन स्थित है, वहां मौजूदा गतिरोध में कोई गोलाबारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वे अभी खेत की सिंचाई कर रहे हैं और अगले 15 दिनों में डीएसआर तकनीक के माध्यम से पूसा 1121 और दूसरी धान की बासमती किस्मों की रोपाई करेंगे।

> **राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर जिलों में 20.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 8.84 लाख खाद्यान्न टन उत्पादन देश को दिया था। राजस्थान के इन सीमावर्ती 10 जिलों में दलहन (मूंग और मोठ) और बाजरा की फसल 20 लाख हेक्टेयर में उगाई जाती हैं**

पंजाब के फाजिल्का, फिरोजपुर, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट जिलों के किसानों ने 2023-24 में 8.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 34.03 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन किया था। वहीं, राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर जिलों में 20.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 8.84 लाख खाद्यान्न टन उत्पादन देश को दिया था। राजस्थान के इन सीमावर्ती 10 जिलों में दलहन (मूंग और मोठ) और बाजरा की फसल 20 लाख हेक्टेयर में उगाई जाती हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 मई को गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में खेती की स्थिति की समीक्षा की थी। उन्होंने खाद और बीज जैसी कृषि सामग्री की उपलब्धता का जायजा लिया था। उन्होंने कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को इन जिलों के किसानों के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए थे। कृषि मंत्रालय को अन्य स्थानों पर धान की रोपाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर उन्हें सीमावर्ती जिलों में पहुंचाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सीमा से 10-15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों की पहचान करें और वहां खेती योग्य जमीन का आकलन करें, इन गांवों में बोई गई खरीफ फसलों के आंकड़े एकत्र कर योजना बनाएं, ताकि किसानों को जरूरी मदद मिल सके।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

रतनपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड रतनपुर

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

सहकारी आंदोलन, किसानों एवं ग्रामीणों को समर्पित प्रगतिशील सहकारी सोसायटी

किसान भाई, अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठावें। समिति कार्यक्षेत्र के पशुपालक, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समिति स्तर पर संपर्क करें।

नाथाराम
अध्यक्ष

नानजीराम
व्यवस्थापक

सहकारिता का ध्येय वाक्य 'एक सब के लिए, सब एक के लिए'सब

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंगाकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 500/- ☐ दो वर्ष रु. 1000/- ☐ तीन वर्ष रु. 1500/- ☐ छह वर्ष रु. 3000/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details : Name: Marwad ka Mitra A/C No.: 11134027554 IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र
संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

वर्तमान में जिले में 417 ग्राम पंचायत व 235 लेप्स, इस वित्तीय वर्ष में 92 व अगले में 93 गठन का लक्ष्य

सहकारिता विभाग की नई पहल, वर्ष 2027 तक हर पंचायत में होगा अपना लैंपस

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बांसवाड़ा । सहकारिता विभाग की ओर से वर्ष 2027 तक बांसवाड़ा जिले की हर ग्राम पंचायत का अपना लेप्स होगा। इन लैम्पस के जरिए क्षेत्र की राशन की दुकानों को संचालन, खाद-बीज का वितरण व लेन-देन संबंधित कार्य किए जा सकेंगे। वर्तमान में जिले में 417 ग्राम पंचायत हैं, इनमें 235 लेप्स हैं। इस प्रकार से 182 लेप्स की और आवश्यकता है। इस वित्तीय वर्ष में 92 व अगले वर्ष 93 का लक्ष्य निर्धारित है। जबकि, बीते वित्तीय वर्ष 60 के गठन का लक्ष्य दिया गया था। सरकार चाहती है कि ग्राम पंचायत में उनके सभी कार्य लैम्पस के जरिए हों, इससे किसानों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़े।

यह होती है प्रक्रिया

केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से सर्वे के बाद प्रस्ताव लिया जाता है। प्रस्ताव का जिला सहकारी विकास समिति की बैठक में अनुमोदन होता है। यह बैठक कलक्टर की अध्यक्षता में होती है। फिर विभागीय स्वीकृति ली जाती है। इसके बाद गठन का प्रक्रिया शुरू होती है। कार्यकारी प्रबंध कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। इसका पंजीयन कराया जाता है। इसके बाद लैम्पस कार्य करने के लिए स्वतंत्र है।

जनजाति अंचल में मिलती है रियायत

लैम्पस गठन के लिए 300 मेंबर की जरूरत होती है। पर सरकार ने आदिवासी क्षेत्र के लिए 150 की सीमा तय है। इसके साथ ही हिस्सा राशि 3 लाख के स्थान पर 1.5 लाख की गई है। जबकि, अमानत राशि 75 हजार के स्थान पर मात्र 50 हजार रुपए निर्धारित है।

लैपस एक मिनी बैंक के रूप में कार्य करते हैं

पड़ोस के राज्य उत्तरप्रदेश में लेप्स एक मिनी बैंक के रूप में कार्य करते हैं। यहां राशन का वितरण के साथ ही अपनी फसल तक लैम्पस के जरिए बेच सकते हैं। समय-समय पर खाद और बीज भी लेप्स के जरिए उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान में भी सहकार गतिविधियों को बढ़ाने के लिए समितियों का गठन हुआ।

एक राज्य में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की व्यवस्था लागू

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली. केंद्र का एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सिद्धांत एक मई से लागू हो गया। एक मई से विभिन्न राज्यों के 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय प्रभावी हो गया और इसके साथ ही देश के 26 राज्य व दो केंद्रशासित प्रदेशों में आरआरबी की संख्या 43 से घटकर 28 रह गई। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के मुताबिक बेहतर प्रशासन, कर्ज प्रवाह और वित्तीय समावेश के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से 26 आरआरबी के विलय का फैसला किया गया है। अप्रैल माह में आरआरबी के विलय की अधिसूचना जारी की गई थी जिस पर एक मई से अमल होना था। पिछले साल नवंबर में इन 26 बैंकों के विलय को लेकर वित्त मंत्रालय ने कवायद शुरू की गई। इससे बैंकों की संचालन लागत में भी कमी आएगी। विलय के बाद ये 28 आरआरबी लगभग 700 जिलों में अपनी 22,000 शाखाओं का संचालन करेंगी। इनमें से 92 प्रतिशत शाखाएं छोटे कस्बे और ग्रामीण इलाकों में हैं। दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के वित्तीय समावेश कार्यक्रम में इन आरआरबी की प्रमुख भूमिका होती है। ग्रामीण इलाके में बैंकिंग सेवा के लिए 1975 में आरआरबी की शुरुआत हुई थी। सभी आरआरबी के पास 2,000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी होगी।

आरआरबी के विलय का यह चौथा चरण

वित्त मंत्रालय के मुताबिक आरआरबी के विलय का यह चौथा चरण है। पहले चरण (2006-2010) में आरआरबी की संख्या 196 से घटाकर 8 कर दी गई थी। दूसरे चरण में (2013-2015) संख्या 8 से घटाकर 56 तो तीसरे चरण (2019-2021) में इसकी संख्या 56 से घटाकर 43 कर दी गई।

- 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय, आरआरबी की संया 43 से घटकर 28 हुई
- सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास 2,000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी होगी
- ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवा के लिए 1975 में हुई थी आरआरबी की शुरुआत

किस राज्य में होगा कौन सा बैंक

उत्तर प्रदेश में मौजूद बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक नाम की इकाई में मिला दिया गया है, जिसका मुख्यालय बैंक आफ बड़ौदा के तहत लखनऊ में है। बंगाल में संचालित बंगीय ग्रामीण विकास, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक में मिला दिया गया है। इसके अलावा देश के आठ राज्यों - बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में दो-दो आरआरबी को एक में मिला दिया गया है।

सांसद ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भोरड़ा का किया निरीक्षण

जालोर। संसदीय क्षेत्र के प्रवास के दौरान भोरड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ उपस्थित पाया गया, जिनसे अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। सांसद ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, सेम्पल टेस्टिंग लेब, वार्ड आदि का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजिका की जांच में पाया गया कि कुछ कर्मचारियों के हस्ताक्षर दो दिन से लंबित हैं। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सांसद ने सीएमएचओ जालोर से दूरभाष पर बात कर तत्काल अवगत कराया तथा निर्देशित किया कि वे स्वयं फील्ड में जाकर अस्पतालों का निरीक्षण करें ताकि सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ आमजन को मिल सके और उन्हें बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इस दौरान चिकित्साकर्मी उपस्थित रहे।

दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । केंद्रीय सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय में राजकाज ई-फाइल एवं ई-डाक पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान कार्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा रविवार को शाखा प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, इसमें अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर से विषय विशेषज्ञ पप्पूराम द्वारा ई-फाइल एवं ई-डाक पर प्रशिक्षण देने के पश्चात राजकाज स्टाफ आई.डी. में आ रही समस्याओं का समाधान किया गया। सीसीबी प्रबंध निदेशक वासुदेव पालीवाल ने समस्त शाखाओं एवं प्रधान कार्यालय के सभी विभागों में ई-डाक व ई-फाइल के कार्य को शत प्रतिशत राजकाज के माध्यम से करने, गोपालन ऋण योजना में गुणवत्तापूर्वक पत्रावलियों तैयार करने, बजट घोषणाओं व सहकार से समृद्धि अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति करने के अलावा ऋणों वितरण व अमानतों के लक्ष्य पूर्ण करने तथा अवधिपार एनपीए ऋणों की वसूली, केवाईसी सहित विभिन्न मानदंडों की पूर्ति करने के निर्देश दिए गए । वही सीसीबी के मुख्य प्रबंधक अमराराम चौधरी द्वारा बैंक के विभिन्न मानदंडों यथा अमानतें, अवधिपार, एनपीए ऋणों की वसूली, केवाईसी, अंकमिलान, ऋण वितरण, लाभदेयता सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा प्रस्तुत की गई। इसके अलावा, अधिशाषी अधिकारी हरिराम पूनिया ने अधिनियमान्तर्गत वसूली व कुर्की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करते हुए ऋणों में डिफॉल्टर सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीसीबी प्रधान कार्यालय एवं शाखाओं के समस्त कार्मिक उपस्थित रहें ।

सीसीबी में डीपीसी करवाने के लिए सहकारिता पंजीयक को दिया ज्ञापन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर, केंद्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर में कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज यूनियन तथा ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा सहकारिता विभाग पंजीयक को ज्ञापन भेजकर विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक शीघ्र आयोजित करने की मांग उठाई गई हैं। इस संबंध में जिला अध्यक्ष अमराराम चौधरी एवं सचिव विक्रमसिंह ने बताया कि केंद्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर में कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति का कार्य गत एक वर्ष से लंबित है एवं बैंक कार्मिक संगठन द्वारा पूर्व में ज्ञापन दिए जाने के उपरांत भी डीपीसी नहीं हो पाई है, इस कारण से कर्मचारियों अधिकारियों में रोष व्याप्त है। वही यूनियन द्वारा ज्ञापन की प्रति सहकारिता विभाग पंजीयक के साथ जिला कलेक्टर बाड़मेर एवं सीसीबी प्रबंध निदेशक तथा संगठन के प्रांतीय महासचिव को भी भेजी गई हैं ।

एमएसपी पर गेहूं की खरीद 250 लाख टन के पार

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अब तक केंद्रीय पूल में 256.31 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। सरकार ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के दौरान 312 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। पिछले साल 30 अप्रैल तक 205.41 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। 2025-26 सीजन के दौरान कुल 21.03 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और कुल एमएसपी के तहत इन्हें 62,155.96 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सभी पांच प्रमुख गेहूं खरीद राज्यों-पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक गेहूं की खरीद की है। खरीद में मुख्य योगदान करने वाले पांचों राज्यों से क्रमशः 103.89 लाख टन, 65.67 लाख टन, 67.57 लाख टन, 11.44 लाख टन और 7.55 लाख टन की खरीद की गई। खरीद के लिए अभी भी पर्याप्त समय बचा हुआ है और इसलिए देश केंद्रीय पूल के लिए पिछले साल के गेहूं खरीद के आंकड़ों को काफी हद तक पार करने की राह पर है। इस बीच, खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि केंद्र मौजूदा खरीद अभियान के समाप्त होने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं आवंटन पात्रता बहाली के बारे में समीक्षा करेगा।

21 लाख किसानों से 62 हजार करोड़ रुपये के गेहूं की खरीदारी, चालू सीजन में 312 लाख टन गेहूं की खरीद का है लक्ष्य

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आकोली में प्रवेश प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी

जालोर । महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आकोली (अंग्रेजी माध्यम) में सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 से 7 तक प्रवेश दिया जायेगा जिसके लिए विद्यालय में 7 मई से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई हैं जिसके तहत इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानाचार्या श्रीमती मीनाक्षी दवे ने बताया कि विद्यालय में प्रवेश से संबंधित जानकारी के लिए सम्पर्क कर सकते है अथवा शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिला कलक्टर प्रदीप के. गावंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बजट घोषणा वर्ष 2025-26 एवं बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि संबंधित विभागीय अधिकारी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यों को पूर्ण करें। बैठक में जिला कलक्टर ने बजट घोषणाओं के तहत जिले में अटल ज्ञान केंद्रों का निर्माण, सरनाऊ में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, केशवना-जालोर में घुमंतु-अर्द्धघुमंतु समुदाय के बच्चों के लिए छात्रावास निर्माण, नून में हवाई पट्टी की

रखरखाव, मरम्मत एवं उन्नयन कार्यों, सांचौर में खेल स्टेडियम की स्थापना सहित विभिन्न बजट घोषणाओं के संबंध में बिंदुवार चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने की भी बात कही। उन्होंने चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, युवा एवं खेल मामले विभाग, पशुपालन विभाग सहित विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं को तय समय सीमा में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. गिरधर सिंह सोढा, जिला रसद अधिकारी आलोक झरवाल, आरसीएचओ डॉ. राजकुमार, पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा, डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र प्रजापति सहित अधिकारी-कार्मिक उपस्थित रहे।

फ्लैगशिप योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करें

जिला कलक्टर प्रदीप के गावंडे ने जिले में केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वामित्व योजना, कुसुम योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, अमृत 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, एन.एफ.एस.ए. की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को इन योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

अगले फसल वर्ष में 35.46 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बेहतर मानूसन बारिश के पूर्वानुमान के चलते जुलाई से शुरू होने वाले 2025-26 फसल वर्ष में भारत 35.46 करोड़ खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य बनाकर चल रहा है। चालू 2024-25 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में सरकार ने 34.15 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा था। खाद्यान्नों में धान, गेहूं, मोटे अनाज और दालें शामिल हैं। चालू 2024-25 फसल वर्ष के खरीफ और रबी सीजन में देश का खाद्यान्न उत्पादन पहले ही 33.09 करोड़ टन तक पहुंच चुका है। ग्रीष्मकालीन (जायद) बोआई के उत्पादन अनुमान अभी जारी नहीं किए गए हैं। फरवरी से जून के बीच बोए जाने वाले ग्रीष्मकालीन सीजन (जायद) में खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में 1.65 करोड़ टन रहा। खाद्यान्नों में सरकार ने फसल वर्ष 2025-26 के लिए 14.73 करोड़ टन चावल उत्पादन का लक्ष्य रखा है। धान तीनों मौसमों में उगाया जाता है। देश में 2024-25 के खरीफ और रबी सीजन में 13.64 करोड़ टन उत्पादन होने का अनुमान है और जायज फसलों के अनुमान जारी होने के बाद यह संख्या और बढ़ जाएगी। अधिकारी ने कहा कि केवल रबी (सर्दियों) के मौसम में उगाए जाने वाले गेहूं के लिए उत्पादन लक्ष्य 11.74 करोड़ टन निर्धारित किया गया है। जबकि मौजूदा फसल वर्ष 2024-25 में कुल उत्पादन 11.54 करोड़ टन रहने का अनुमान है।

सहकारिता का जिला स्तरीय कॉमन कैडर लागू करने की मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

उदयपुर । केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक भर्ती की परीक्षा आयोजित होने के उपरांत पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों चयन एवं भर्ती सेवानियम 2022 के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक संवर्ग के 20 प्रतिशत पद व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित होने का प्रावधान होने के बावजूद आज दिन तक इस प्रक्रिया में कोई पहल नहीं होने पर चिंता जाहिर करते हुए राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हनुमानसिंह राजावत ने सरकार एवं सहकारिता विभाग से जल्द चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग उठाई हैं, दरअसल, राजावत राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन की संभाग स्तरीय बैठक में भाग लेने उदयपुर पहुंचे, तब उन्होने आयोजित मीटिंग के दौरान अपने संबोधन में यह बात कही । वही उन्होने ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चयन कमेटी के माध्यम से नियमितीकरण से वंचित पात्र कर्मचारियों का अविलंब सेवानियम के अनुरुप स्थाईकरण करने की प्रक्रिया संपन्न करवाने के अलावा वर्तमान परिवेश में पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़ी समस्याओं का समाधान करवाने हेतु जिला स्तर पर सहकारिता का कॉमन कैडर लागू करवाने की मांग पुनः विभाग के संज्ञान में लाने की बात दोहराई हैं । इस दौरान यूनियन महासचिव महीपाल सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वाल सिंह सिसोदिया, कारीलाल मीणा, उदयपुर सम्भाग उपाध्यक्ष नरेन्द्र सिंह शक्तावत, संगठन मंत्री दिलीप जैन, बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह, उदयपुर जिलाध्यक्ष गोपाल पालीवाल, प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष नंदलाल रेदास, प्रदेश संयोजक हेमन्त कुमार शर्मा, भिंडर व्यवस्थापक देवदत्त शर्मा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलुमबर जिलों के व्यवस्थापक मौजूद रहें ।

15 मई तक मांगो का समाधान नहीं होने पर बहिष्कार की चेतावनी

संभाग स्तरीय बैठक के दौरान यूनियन की ओर से विभिन्न मांगो से सहकारिता विभाग को अवगत कराने के बावजूद वाजिब मांगों का 15 मई तक निस्तारण नहीं होने पर यूनियन की ओर से पूरे प्रदेश में अल्पकालीन फसली ऋण वितरण एवं वसूली कार्य सहित पैक्स कंप्यूटराईजेशन एवं खाद-बीज सहित समस्त कार्यो का सामूहिक बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

नगर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड नगर

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

सहकारी आंदोलन, किसानों एवं ग्रामीणों को समर्पित प्रगतिशील सहकारी सोसायटी

किसान भाई, अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठावें। समिति कार्यक्षेत्र के पशुपालक, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समिति स्तर पर संपर्क करें।

सोहनलाल
अध्यक्ष

अचलाराम चौधरी
व्यवस्थापक

सहकारिता का ध्येय वाक्य 'एक सब के लिए, सब एक के लिए'सब '

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर (जिला-जालोर) गुरुवार, 15 मई 2025
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

राजस्थान विधानसभा सचेतक जोगेश्वर गर्ग की उपस्थिति मे योजना के तहत बैंक द्वारा नो-ड्यूज के साथ-साथ भूमि रहन मुक्ति आदेश जारी

जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक के ऋणी किसानों को मिलेगी 67.25 करोड़ रूपए की राहत

25 वर्ष पुराने ऋण खाता के ऋणी नारायणसिंह के बैंक का कुल बकाया ऋण 15.50 लाख रू. के पेटे 3.50 लाख रूपए जमा करवाए, नारायणसिंह पुत्र खीमसिंह को इस योजना के तहत 12 लाख की ब्याज राहत प्राप्त हुई।

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों को राहत देने के लिए की गई बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना के तहत शुक्रवार को मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा जोगेश्वर गर्ग की उपस्थिति में जालोर सहकारी भूमि विकास की भीनमाल शाखा के 25 वर्ष पुराने ऋण खाता के ऋणी नारायणसिंह पुत्र खीमसिंह के बैंक का कुल बकाया ऋण 15.50 लाख रू. के पेटे 3.50 लाख रूपए जमा करवाए गए। नारायणसिंह पुत्र खीमसिंह को इस योजना के तहत 12 लाख की ब्याज राहत प्राप्त हुई। इस दौरान राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बैंक द्वारा जारी रसीद प्रदान कर ऋणी किसानों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की बात कहीं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बकाया ऋण जमा कराने वाले किसानों को बैंक द्वारा नो-ड्यूज के साथ-साथ भूमि रहन मुक्ति आदेश भी जारी किया जाएगा। मुख्य सचेतक ने कहा कि बैंक के सभी अवधिपार ऋणियों को 100 प्रतिशत अवधिपार ब्याज राहत की योजना का लाभ मिले तथा योजना के प्रचार-प्रसार करने की बात कही। इस योजना के तहत जालोर भूमि विकास बैंक में कुल पात्र ऋणी 5 हजार 769 है जिनको ऋण पर कुल 67.25 करोड़ रूपए की राहत देते हुए 31.69 करोड़ रूपए जमा करवाए जाने है। ऋण निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना के तहत किसान को मूल बकाया ऋण की 25 प्रतिशत राशि 30 जून तक भूमि विकास बैंक जालोर में जमा करवाने पर ही लाभ देय होगा। इस दौरान नारायणसिंह एमडी सीसीबी जालोर, बैंक सचिव एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जालोर सुनील वीरभान, रवि सोलंकी, तकनीकी सहायक जमना मेघवाल, किसान तथा बैंक सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया।

तारबंदी करने के दौरान किसान पेड़ों को न काटे-मुख्य सचेतक

मुख्य सचेतक द्वारा तारबंदी हेतु ऋण योजना के तहत 45 हजार रूपए का चेक वसनाराम पुत्र भीखाराम को प्रदान कर ऋण वितरण का शुभारंभ किया गया। ऋण चेक वितरित करते हुए गर्ग ने किसानों से तारबंदी करवाने के दौरान पेड़ों की कटाई नहीं करने की बात कही।

सोलंकिया तला ग्राम सेवा सहकारी का मामला

पैक्स कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद शुरू नहीं हो पाया फसली ऋण वितरण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर । जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय के निर्देश पर पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में गो-लाइव से वंचित पैक्स में फिलहाल अल्पकालीन फसली ऋण वितरण पर रोक लगाई हुई हैं, इसमें जिले की सोलंकिया तला ग्राम सेवा सहकारी समिति भी शामिल हैं, हालांकि यह ग्राम सेवा सहकारी समिति गो-लाइव हो चुकी हैं, लेकिन केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से ऋण वितरण प्रारंभ नहीं करने से किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं, इस भीषण गर्मी के दौर में ग्राम सेवा सहकारी समिति से जुड़े किसान संबंधित शाखा से लेकर समिति मुख्यालय पर खरीफ सीजन की बुवाई का ऋण लेने के लिए चक्कर लगा रहें हैं । जबकि ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक का कहना हैं कि सहकारी समिति को गो-लाइव हुए करीबन एक माह होने को आया हैं, लेकिन सीसीबी की ओर से ऋण वितरण प्रक्रिया पर लगे प्रतिबंध को हटाया नहीं जा रहा हैं, जिससे किसानों को परेशानी हो रही हैं । गौरतलब हैं कि जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की शेरगढ़ शाखा अंतर्गत संचालित सोलंकिया तला ग्राम सेवा सहकारी समिति 1126 किसान ऋणी सदस्य जुड़े हुए हैं, जिनको खरीफ सीजन के दौरान लगभग 6 करोड़ तक का ऋण सहकारी समिति की ओर से मुहैया कराया जाता हैं ।

लोन नहीं चुकाने वाले किसानों पर लगाम के लिए सरकार ने निकाला तोड़

किसानों का क्रेडिट स्कोर बनेगा, लोन नहीं चुकाया तो खाद-मुआवजा और लोन पर रोक

ओम प्रकाश शर्मा
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, राज्य सरकार ऐसे किसानों पर लगाम कसने जा रही है, जो सहकारी बैंकों से लोन ले तो लेते हैं लेकिन चुकाते नहीं हैं। सरकार के पास इस समस्या के अब तक दो ही समाधान थे-कर्जमाफी या फिर कुर्की। अब सरकार किसानों का क्रेडिट स्कोर तैयार करेगी। यदि यह स्कोर बिगड़ा, तो संबंधित किसान पर कई पाबंदियां लागू होंगी। उसे ब्याज मुक्त फसली लोन नहीं मिलेगा। मुआवजा, खाद आदि मिलने पर भी रोक लग जाएगी। दरअसल, बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं जिन्होंने भूमि विकास बैंक से लोन लिया लेकिन चुकाया नहीं। ऐसे में उन किसानों पर बकाया राशि बढ़ती गई। किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने समझौता स्कीम लॉन्च की, जिसमें ब्याज राशि सरकार वहन करेगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे पहले देखने में आया था कि समझौता स्कीम के बाद भी कई किसान लोन नहीं चुकाते, इसलिए सरकार ने वसूली प्रक्रिया में सिबिल का प्रावधान किया है। छूट के बाद भी लोन नहीं चुकाने वाले किसानों का क्रेडिट स्कोर बिगड़ेगा। सिविल एक क्रेडिट ब्यूरो है, जो व्यक्तियों और कंपनियों के क्रेडिट इतिहास को रिकॉर्ड करता है।

30 हजार किसानों का लोन अवधिपार, वसूली नोटिस दिए जा रहे

नए नियमों में तहत सबसे पहले भूमि विकास बैंकों के उन कर्जदार किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं, जिन्होंने लोन नहीं चुकाया। नोटिस में क्रेडिट स्कोर बिगड़ने की चेतावनी दी गई है। 30 हजार किसान ऐसे हैं, जिनका लोन अवधिपार हो चुका है। इन पर मूल राशि, अवधिपार ब्याज व दंडनीय ब्याज सहित 846.32 करोड़ बकाया हैं। सरकार ने 515 करोड़ रुपए के अवधिपार ब्याज व दंडनीय ब्याज पर छूट दी है। मुख्यमंत्री ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना में छूट शेष राशि जमा कराने वाले किसानों को ही मिलेगी। भूमि विकास बैंक के प्रशासक प्रदीप खंडेलवाल ने बताया कि योजना लागू होने के साथ ही करीब 10 हजार किसानों को वसूली नोटिस दिए गए हैं।

सिबिल खराब हो तो ये नुकसान
- बैंक से लोन लेने में समस्या।
- विदेश यात्रा में समस्या, वीजा प्रॉब्लम।
- वह व्यक्ति किसी की बैंक में वित्तीय गारंटी नहीं दे सकता
- स्वयं के साथ परिवार के सदस्यों को भी वित्तीय कार्यों में समस्या।
- क्रेडिट कार्ड लेने में परेशानी आएगी।

(कर सलाहकार संदीप गुप्ता के अनुसार)

कर्ज माफी के बाद वसूली में गिरावट

सहकारी बैंकों से किसानों को कई स्कीम में लोन दिया जाता है। गत वर्षों में भाजपा व कांग्रेस सरकार ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों से लिए जाने वाले अल्पकालीन फसली ऋण योजना में कर्ज माफी की गई थी। जानकार बताते हैं कि इसके बाद कई योजनाओं में ऋण वसूली धीमी हुई है।

सिबिल के साथ और भी बाध्यता

ब्याज मुक्त फसली ऋण नहीं मिलेगा। क्रय विक्रय सहकारी समिति से खाद नहीं मिलेगी। राज्य सरकार से मिलने वाला मुआवजा नहीं मिलेगा। सहकारी संस्थाओं में चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी

सरकार ने दो सौ करोड़ रुपए ब्याज

अनुदान के लिए देने की घोषणा की है। इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है। इसका मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे।

- गौतम कुमार दक, सहकारिता मंत्री

सहकारी समितियों को सक्रिय करने के निर्देश

नागौर, कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने की। बैठक का उद्देश्य जिले में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना था। कलेक्टर ने पैक्स के कंप्यूटरीकरण, ग्राम पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय सेवा समितियों के गठन, अनाज भंडारण के लिए गोदाम निर्माण और पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने की योजनाओं की समीक्षा की। जन औषधि केंद्रों के संचालन पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने निष्क्रिय सहकारी समितियों को फिर से सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के कार्यक्रम समय पर पूरे किए जाएं। सभी सहकारी समितियों में डाटा कैप्चरिंग बेहतर और संयोजित तरीके से हो। इससे समितियों का कामकाज मजबूत होगा। कलेक्टर ने तय समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही राज्य स्तर की तालिका में नागौर जिले की स्थिति सुधारने पर जोर दिया।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

कल्याण ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड मालवाड़ा

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

सहकारी आंदोलन, किसानों एवं ग्रामीणों को समर्पित प्रगतिशील सहकारी सोसायटी

किसान भाई, अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठावें। समिति कार्यक्षेत्र के पशुपालक, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समिति स्तर पर संपर्क करें।

राणसिंह देवल
अध्यक्ष

जब्बरगिरी गोस्वामी
व्यवस्थापक

सहकारिता का ध्येय वाक्य 'एक सब के लिए, सब एक के लिए'सब '

फसली ऋण से प्रतिबंध नहीं हटा तो किसानों का ऋण हो जायेगा अवधिपार

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर, जिले में पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत गो-लाइव की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने पर केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से जिले की 68 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में प्रतिबंधित किए गए अल्पकालीन फसली ऋण वितरण कार्य में छूट देकर ऋण वितरण शुरू करने की मांग राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन यूनिट जालोर की ओर से उठाई गई हैं, यूनियन जिला अध्यक्ष हनुमानसिंह राजावत ने सीसीबी प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर जिले में अल्पकालीन फसली ऋण योजना पर लगी रोक में 15 जुलाई 2025 तक शिथिलता प्रदान कर ऋण वितरण कार्य शुरू करने का पत्र में जिक्र कर बताया कि इस विस्तारित अवधि के दौरान अल्पकालीन फसली ऋण प्रतिबंध वाली समितियों में पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना कार्य को विशेष प्राथमिकता देते हुए पूर्ण करने के साथ अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति की जाएगी । वही पत्र के मुताबिक अल्पकालीन फसली ऋण वितरण एवं वसूली को प्रतिबंधित किए जाने से किसानों का ऋण अवधिपार होने के साथ किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना का लाभ समय पर नहीं मिल पाएगा, जिससे किसानों को ब्याज के रूप में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, इतना ही नहीं ऋणी किसान को अन्य कई योजनाओ से वंचित रहना पड़ सकता है।

राजस्थान में 18 से 20 जून तक पहुंच सकता है मानसून

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली. इस बार मानसून जल्दी दस्तक देगा। इसके संकेत मिलने लगे है। मानसून मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग और निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच गया। तीन-चार दिन में यह और आगे बढ़ सकता है। इसके 27 मई को केरल पहुंचने के आसार है। वहीं मौसम विभाग (आइएमडी) के मुताबिक राजस्थान में मानसून की एंट्री 18 से 20 जून तक हो सकती है। इससे पहले कई राज्यों में बारिश हो सकती है। पिछले दो दिन में निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश हुई है। आइएमडी ने बताया कि अगले तीन-चार दिन में दक्षिण अरब सागर और दक्षिण बंगाल की खाड़ी के अधिकतर हिस्सों में मानसून आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। छत्तीसगढ़ में 15 मई तक आंधी, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में 16 मई तक बारिश होगी। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 14 से 15 मई, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 14 मई और झारखंड में 15-16 मई को बारिश का अनुमान है। केरल में 27 मई तक बारिश की संभावना है। आइएमडी इससे पहले मानसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान जता चुका है। उसने अल नीनो की स्थिति को खारिज कर दिया था, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम बारिश से जुड़ी है। भारत के कृषि क्षेत्र के लिए मानसून संजीवनी है। यह क्षेत्र 42 फीसदी आबादी को आजीविका प्रदान करता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 18 फीसदी का योगदान देता है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून आमतौर पर एक जून को केरल में दस्तक देता है। अगर इस साल यह समय से पहले पहुंचता है तो 2009 के बाद पहली बार ऐसा होगा। मानसून ने 2009 में 23 मई को दस्तक दी थी। भारत में मानसून के आगमन की आधिकारिक घोषणा तब होती है, जब यह केरल पहुंचता है। दक्षिण-पश्चिम मानसून 8 जुलाई तक पूरे देश में फैल जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

धानोल ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धानोल

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

सहकारी आंदोलन, किसानों एवं ग्रामीणों को समर्पित प्रगतिशील सहकारी सोसायटी

किसान भाई, अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठावें। समिति कार्यक्षेत्र के पशुपालक, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समिति स्तर पर संपर्क करें।

पूरणसिंह देवड़ा
अध्यक्ष

गणपतसिंह बालोत
व्यवस्थापक

सहकारिता का ध्येय वाक्य 'एक सब के लिए, सब एक के लिए'सब '

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कस्टम हायरिंग सेंटरों के लिए खरीदे

ट्रैक्टर का एक जैसा मॉडल और पावर, फिर भी दरों में भारी अंतर खरीद पर उठे सवाल

हरि सिंह गुर्जर
Www.marwadkamitra.in

झालावाड़। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कस्टम हायरिंग सेंटरों के लिए ट्रैक्टर खरीद में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। जिले की दस समितियों द्वारा पिछले साल मार्च व अप्रेल में खरीदे गए एक ही मॉडल के ट्रैक्टरों की कीमतों में 15 से लेकर 42 हजार रुपये तक का अंतर पाया गया है, जबकि सभी ट्रैक्टर एक ही कंपनी की एक ही मॉडल है। मजेदार बात यह है कि ये सभी ट्रैक्टर एक ही डीलर से खरीदे गए है। जानकारों के अनुसार किसानों को किराए पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने योजना बनाई थी। इसके तहत झालावाड़ केंद्रीय सहकारी बैंक ने 41 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए। इनमें से दस समितियों के लिए वर्ष 2023-24 में ट्रैक्टर खरीदे गए, लेकिन इनकी खरीद की दरों में बड़ा अंतर उजागर हुआ है। जानकारों के अनुसार अनुसार बाजार में अन्य कंपनियों के 46 एचपी ट्रैक्टर 7.70 लाख रुपए में उपलब्ध हैं, इसी पावर के एक कंपनी के ट्रैक्टरों की खरीद 8.28 लाख से 8.71 लाख रुपए तक में की गई। प्रत्येक ट्रैक्टर पर 80 हजार से 1 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राशि अदा की गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है।

बड़ा सवाल

जब सभी ट्रैक्टर एक ही मॉडल और कंपनी के हैं। ये सभी एक ही समयावधि में खरीदे गए हैं तो कीमतों में इतना अंतर क्यों। कहीं न कहीं यह सहकारी बैंक और संबंधित समितियों के स्तर पर मिलीभगत की ओर इशारा करता है।

यह है खरीद का विवरण

सहकारी समिति		खरीद तिथि		मूल्य
रूडलाव	-	8 मार्च	-	8,28,861
नाहरघट्टा	-	8 मार्च	-	8,70,165
किटिया	-	7 मार्च	-	8,28,861
जूनाखेड़ा	-	15 मार्च	-	8,56,488
भैंसानी	-	11 मार्च	-	8,70,165
जनता कनवाड़ा	-	7 मार्च	-	8,28,861
जावर	-	3 अप्रेल	-	8,56,488
सरेड़ी	-	3 अप्रेल	-	8,71,849
चंदीपुर	-	3 अप्रेल	-	8, 56,488
कोलूखेड़ी	-	3 अप्रेल	-	8,56,488

उद्देश्य से भटक गई योजना

राज्य सरकार की योजना थी कि किसानों को सस्ते किराए पर ट्रैक्टर, थ्रेशर, बीज ड्रिल, रोटोवेटर आदि उपकरण दिए जाएं ताकि वे खेती के आधुनिक साधनों का लाभ उठा सकें। लेकिन जब उपकरणों की खरीद में ही भ्रष्टाचार हो तो इसका लाभ जमीनी स्तर तक कैसे पहुंचेगा

एक ही दिनांक और एक ही कंपनी का ट्रैक्टर सहकारी बैंक द्वारा खरीदा गया है। उसमें अगर अंतर आ रहा है तो गलत है। इसकी जांच करवाई जाएगी। यदि गड़बड़ी पाई गई तो वसूली की कार्रवाई होगी।

अजय सिंह राठौड़, जिला कलक्टर झालावाड़

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म परावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।